

संपादकीय

उनके राम, अपने राम,
सबके राम, हमारे ‘राम’

आज पूरा देश ही नहीं कमावेश दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा राममय होता जा रहा है। जैसे-जैसे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्रीराम मंदिर के भव्य उद्घाटन का समय नजदीक आ रहा है, अनेक जमातों के कई उपद्रवियों ने मुसलमानों से अनुचित अपील की है, उनसे घर के अंदर रहने और ट्रेन यात्रा से बचने का आग्रह किया है। ऐसी कार्रवाइयों के बावजूद, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये गुरुराह अपीलें देश की एक जुट भावना को प्रतिबिधित नहीं करती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार कर लिया है। देश एकजुट है और कुछ शरारती तत्वों की राजनीतिक चालें सद्भाव और स्वीकार्यता के समग्र परिवेश पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में वैश्विक स्तर पर 7,000 से अधिक अतिथियों के आने का अनुमान है, कम से कम एक महीने तक 3-5 लाख दैनिक आगंतुकों की उम्मीद है। तीर्थात्रियों की यह वृद्धि विभिन्न व्यवसायों के लिए आकर्षक अवसर उपलब्ध करवाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्त तिथि को दोपहर 12:15 बजे के आसपास अनुष्ठान करेंगे और 2.77 एकड़ में फैले नगर शैली के मंदिर में गुलाबी बलुआ पत्थर का निर्माण और भगवान राम का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक उल्लेखनीय शालिग्राम पत्थर है। तीन मंजिल की संरचना में भगवान राम और हनुमान के लिए समर्पित स्थान, एक संग्रहालय, एक यज्ञशाला, एक सामुदायिक रसोई और एक चिकित्सा सुविधा शामिल है, जो 67 एकड़ में फैली हुई है। मंदिर के इतिहास में 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा इसका विध्वंस, उसके बाद मस्जिद निर्माण और 1992 में विध्वंस, भारत सरकार द्वारा गठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दखेरेख में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के पक्ष में अयोध्या विवाद का निपटारा शामिल है। विचारणीय है कि पिछले 495 वर्षों से चला आ रहा अयोध्या श्री राम जन्मभूमि विवाद सन् 1528 ई. में भगवान् श्री राम की जन्मभूमि माने जानेवाले स्थान पर एक मस्जिद के विवादित निर्माण के साथ उत्पन्न हुआ था। इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, जिसके अंगेजों को सन् 1859 ई. में बड़े लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए सीमित पहुंच प्रदान की गई। सन् 1949 ई. में विवाद तब और बढ़ गया, जब मस्जिद के अंदर मूर्तियाँ पाई गईं, जिसके बाद कानूनी लड़ाई आरंभ हुई और अंततः सन् 2019 ई. में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हिंदुओं को 2.77 एकड़ जमीन आवंटित की गई। 6 दिसंबर 1992 ई. की विवादास्पद घटनाओं में विवादित ढाँचे का विध्वंस हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। सन् 2010 ई. में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को सुनी वक्फ बोर्ड, श्री रामलला विराजमान और निर्माणी अखाड़े के बीच विभाजित कर उन्हें आवंटित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सन् 2011 ई. में इस फैसले पर रोक लगा दी, सन् 2017 ई. में अदालत के बाहर समाधान का आग्रह किया। हालाँकि, कोई समाधान नहीं होने पर, अदालत ने सन् 2019 में दैनिक सुनवाई शुरू की, जिसका समाप्त 9 नवंबर, 2019 को राम जन्मभूमि के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसले में हुआ। सन् 2020 में 28 वर्षों के बाद, मूर्तियों को स्थानांतरित किया गया और 5 अगस्त को निर्माण शुरू हुआ। अंततः 22 जनवरी, 2024 को रामलला के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा, जो अब दैनिक विध्वंस में रह चुका है, विवादित भूमि के विर्यापक रूप से निर्माण हो रहा है।

भारत के इतिहास में इस लब और विवादोंपद अध्ययन के नियायक समापन का प्रतीक है। देश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका उसके निर्णयों की व्यापक स्वीकृति की माँग करती है, भले ही वे किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के पक्ष में हों, ताहे वह हिंदू हों या मुस्लिम। हिंदू समुदाय के पक्ष में राम मंदिर के फैसले के मामले में, हर किसी के लिए फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, यह समझते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी कानूनी प्रणाली में अंतिम निर्णय है। इस नजरिए से संभावित दंगों की निराधार अफवाहों को स्पष्ट रूप से खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि शान्तिपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना सव॑परि है। यहाँ यह जानना और पहचानना अनिवार्य है कि यदि निर्णय मुस्लिम समुदाय के पक्ष में होता, तो वही सम्मान और स्वीकृति आवश्यक होती। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में न्यायपालिका की पावत्रता को कायम रखना समाजिक सङ्दर्भ के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत संबद्धताओं की परवाह किए बिना एकता पर जोर देना, न्याय के सिद्धांतों और कानून के शासन के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है, जिससे देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अल्पसंख्यक प्रक्रोड़ ने %दीपोत्सव% नामक एक हृदयस्पर्शी एवं समावेशी पहल की है, जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अंदर भगवान् राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देशभर में 1,200 दरगाहों और मस्जिदों को मिट्टी के दीयों से रोशन करने की योजना बना रही है। 12 से 22 जनवरी तक निर्धारित यह कार्यक्रम एकता और समावेशी समाज के लिए एक सुंदर भाव का प्रतीक है। भाजपा अल्पसंख्यक विंग के संयोजक यासर जिलानी ने साझा किया, हमने देश भर में 1,200 छोटी/बड़ी मस्जिदों, दरगाहों और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों की पहचान की है, जहाँ हम दीये जलाएंगे। अकेले दिल्ली में, जामा मस्जिद और निजामुदीन दरगाह सहित 36 महत्वपूर्ण स्थानों से संबद्ध लोग भाग लेंगे। 30 दिसंबर को अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को दीये जलाने का आह्वान किया, जिससे इसे देशव्यापी दिवाली उत्सव में बदल दिया गया। उन्होंने 14 से 22 जनवरी तक तीर्थ स्थलों और मंदिरों में स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित किया। सांप्रदायिक सङ्दर्भ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह विचारशील पहल, विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातीयताओं के लोगों को एक साथ लाने की भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जैसे ही भगवान राम का %प्राण प्रतिष्ठा% समारोह सुरु होता है, जो एक महत्वपूर्ण घटना है, राष्ट्र सामूहिक रूप से एकता, भाईचारे और सङ्दर्भ की भावना का जश्न मनाता है। सभी धर्मों को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने में, हम भारत के सच्चे लोकाचार को अपनाते हैं, जो उन मल्यों का प्रतीक है जो हम सभी को एकजट

बात अब मीडिया ट्रायल और अदालती फैसले की आलोचना से कहीं आगे फैसले देने वाले जजों की ट्रोलिंग तक आन पहुंची है। यही कारण है कि हाल में भोपाल में आयोजित दसवें मप्र न्यायाधीश सम्मेलन में जिला न्यायालयों के जजों ने यह मुझ जोर शोर से उठाया और बरिष्ठ जजों से मार्गदर्शन मांगा कि न्यायाधीशों की ट्रोलिंग पर उहें क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों की ट्रोलिंग भी अदालती अवमानना हो सकती है या नहीं? सोशल मीडिया में किसी खास वैचारिक एजेंडे अथवा पूर्वाग्रह दुग्राह के चलते गढ़े जाने वाले नरेटिव, न्यूसेंस और जजों की व्यक्तिगत आलोचना को किस रूप में लिया जाना चाहिए? क्योंकि भारत में सोशल मीडिया की नकेल कसने के लिए बहुत कड़े कानून नहीं है। ऐसे कानून बन भी जाएं तो फिर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का क्या होगा? वैसे भी कई लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया दरअसल जनता की आवाज है। लाख आलोचना के बावजूद इसे दबाया नहीं जा सकता। सम्मेलन में शामिल देश के सुर्प्रीम कोर्ट के ज्यादातर न्यायाधीशों की राय यही थी कि जजों की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के मामलों को फिलहाल इन्नोर (अनदेखा) करना ही बेहतर है। भाव यही कि ऐसे तत्वों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। हालांकि यह उत्तर भी कई सवालों से भरा है। यूं न्यायपालिका के सामने नई चुनौती अर्थात् विश्यल इंटेलिजेंसल एआई की भी है, लेकिन उसका मामला थोड़ा अलग है। न्यायाधीशों पर सोशल मीडिया के हमलों का मामला ज्यादा संवेदनशील इसलिए है क्योंकि अदालती फैसले समाज में न्याय की

इंटरनेट अर्थव्यवस्था: उत्साहित करने के साथ डराती भी है तीन दशक की यह यात्रा

तास साल पहल का बात ह। जनवरा का ग्यारहवा दिन था। जब सरकार, शिक्षा और संचार क्षेत्र की दो दर्जन से ज्यादा हस्तियां कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में आयोजित एक भविष्य-उन्मुखी सम्मेलन में शामिल हुई थीं, जिसका नाम था- 'सुपर हाईवे समिट'। इससे जुड़ा एक दिलचस्प वाकया है। सम्मेलन का आयोजन दरअसल टेलीविजन, आर्ट्स व साइंसेज अकादमी के रिचर्ड फँक कर रहे थे, जिन पर चुटकी लेते हुए तकालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर ने कहा, 'जो टेलीविजन पर नहीं आया, समझो हुआ ही नहीं।' ठीक ऐसा ही कुछ आप आज 2024 के लिए भी कह सकते हैं कि, जो इंटरनेट व सोशल मीडिया पर नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। दुनिया में इंटरनेट के विकास का अलबता एक लंबा इतिहास रहा है। एक तरह से देखें, तो सुपर हाईवे समिट के साथ ही इंटरनेट के सुपरहाईवे और इंटरनेट आधारित इनकार्नोमी की शुरुआत देखी जा सकती है। 1994 में एनसीएस एमोजैक और नेटस्केप के बेब ब्राउजर शुरू होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सप्लोरर यूजर्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी बल्ट्ड वाइड बेब लाया। इस तरह एक छोटी-सी शुरुआत थोड़ा झिझकते हुए वैश्विक इंटरनेट इनकार्नोमी की तरफ बढ़ी। 2024 में विश्व की औसत आयु करीब साढ़े 30 वर्ष अनुमानित है। इससे जाहिर होता है कि दुनिया की आठ अरब से ज्यादा आबादी का करीब आधा हिस्सा इंटरनेट के युग में ही पैदा हुआ है। पूरी दुनिया में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या 5.3 अरब से ज्यादा है और यह लगातार बढ़ भी रही है। गूगल जो एक संज्ञा है, जबाब खोजने की क्रिया बन गई है। बेब (जाल) के बल वही नहीं रह गया, जो मकड़ियां बुनती हों। फिल्में व संगीत स्ट्रीम होने लगे हैं। सामाजिकता

सियासतः इंडिया गठबंधन की बढ़ती मुश्किलें प्राण प्रतिष्ठा पर फिर धारा के विपरीत

चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा भले अभी दो महीने बाद करेगा, पर देश की पूरी राजनीति इसके ईर्द-गिर्द धूम रही है। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रमुख समूह भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग तथा 'ईडिया' गठबंधन हैं। इन दो प्रमुख समूहों की स्थिति के आकलन से लोकसभा चुनाव की अस्पष्ट ही सही, लेकिन तस्वीर जस्तर बन जाती है। भाजपा ने कहा है कि वह 2024 में 50 फीसदी वोट का लक्ष्य लेकर बढ़ रही है। जबकि, 'ईडिया' गठबंधन के घटक दलों ने श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण तुकराकर समय की धारा को फिर न पहचानने का प्रमाण दिया है। खुद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी और मलिकार्जुन खरगे द्वारा निमंत्रण तुकराने पर दुख भी प्रकट कर दिया है। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तथा उनके नेतृत्व में भाजपा के सत्ता में आने का मूल कारण ही हिंदुत्व प्रेरित राष्ट्रीय चेतना तथा भारत को अपनी पहचान के साथ विश्व के उच्चतम शिखर पर देखने का जनता के अंदर पैदा हुआ प्रबल भाव ही था। 2004 में सत्ता में आने पर यूपीए अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी के प्रभाव में चलने वाली मनमोहन सिंह सरकार ने स्वयं को सेव्युलर साक्षित करने के लिए सच्चर आयोग से लेकर अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन तथा रामसेतु और राम को कल्पना का विषय न्यायालय में बताकर अपनी स्थिति धीरे-धीरे कमजोर करनी शुरू कर दी थी। सत्ता से बाहर होने के बावजूद कांग्रेस, जिसका वास्तविक नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथों में दिखता है, प्रकारांतर से इस नीति को आगे बढ़ा रही है। एक ओर देश का राममय वातावरण और दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़े न्याय यात्रा की तुलना करें, तो दिख जाएगा कि विचार के स्तर पर



‘इंडिया’ गठबंधन अब तक एक काई नहीं बन सका है, जिसका प्रमाण बीती 12 जनवरी को आयोजित इसकी बैठक में भी मिला, जिसमें गठबंधन के कई प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर कोई विभाजन नहीं है। चुनाव में नेतृत्व का चेहरा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नरेंद्र मोदी के समानांतर विपक्ष में कोई नेता नहीं, जिसे जनता उनके समक्ष या बड़ा मान सके। ‘इंडिया’ गठबंधन में नेतृत्व को लेकर व्यापक मतभेद हैं, क्योंकि अनेक नेताओं की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तीसरी पारी में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा 2047 तक वैश्विक महाशक्ति बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। वर्तीं, विपक्ष मोदी, संघ और विपक्षी नेताओं ने जिस तरह सनातन और हिंदुत्व से लेकर उत्तर के राज्यों को गोमूत्र की संज्ञा देने तथा उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन पैदा करने संबंधी बयान दिए हैं, उनसे देश के बहुमत में जो नाराजगी पैदा हुई है, उसे संतुलित करने के लिए जितने बड़े मुद्दे और जैसे चेहरे चाहिए, विपक्ष में उनका नितांत अभाव है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में विजय से यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 2019 से बेहतर प्रदर्शन करेगी। 2019 में भाजपा द्वारा जीती गई 303 लोकसभा सीटों में तेलंगाना से चार मिली थी, हालांकि तेलंगाना के इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें मिली हैं। कर्नाटक में पिछले लोकसभा चुनाव में सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस के पास मात्र एक सीट थी। भाजपा के लिए अच्छी बात यह है कि 2023 विधानसभा चुनाव में यहाँ उसकी सीटें घटी, बोट नहीं। हाँ, कांग्रेस के मतों में पांच फीसदी की बढ़ोतरी अवश्य हुई। दोनों राज्यों में मुसलमानों का मत कांग्रेस के पक्ष में ध्वनीकृत हुआ है। मुस्लिम मत खिसकने के कारण ही कर्नाटक में जद-एस भाजपा के साथ आया है। भाजपा तमिलनाडु पर खास ध्यान दे रही है और चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के अलावा रामनाथपुरम से भी चुनाव लड़ सकते हैं। यदि ऐसा होता है और तमिलनाडु में स्थिति बदलती है, तो इसका असर पूरे दक्षिण भारत में होगा और यदि ऐसा नहीं हुआ, तब भी भाजपा जितना ध्यान दक्षिण पर दे रही है, वह बिल्कुल अप्रभावी तो साक्षित नहीं हो सकता।

सारिल माड्या म जजा का ट्रोलिंग और कुछ नैतिक सवाल

सचालित करने का दिशानिर्देश और सुसृत्रा भी मिलती है। अदालती फैसले हमेशा निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रतीत हों, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उन फैसलों की आलोचना तार्किक और कानूनी आधार पर ही की जा सकती है। लेकिन जब ऐसे फैसलों के पीछे न्यायाधीश के विवेक, न्यायिकता अथवा पूर्वग्रह को लेकर सवाल उठाए जाने लगें, उनकी भद्रे ढंग से ट्रॉलिंग की जाए तो तब न्यायाधीशों का विचलित होना स्वाभाविक है। सम्मेलन में शामिल कई जजों ने कहा कि वर्तमान में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे कि वाट्सएप रूप और फेसबुक पर हमारे विश्वद्व अमर्यादित बातें होती हैं। जिन्हें फैसला पसंद नहीं आता, वे भ्रम फैलाते हैं। भद्रे कमेंट करते हैं। क्या ऐसा करने वालों पर हम (न्यायाधीश) कर्टेम्स्ट ऑफ कोर्ट (अदालत की अवमानना) की कार्रवाई कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जज जिस्टिस अभ्यु एस ओक ने कहा कि न्यायाधीश सोशल मीडिया की ट्रॉलिंग से न तो डरें और न हीं किसी एंजेंडे के तहत गढ़े जाने वाले नैरेटिव से प्रभावित हों। इसे सिफ़ इनोर करें, क्योंकि सोशल मीडिया की कोई अकाउंटेबिलिटी कि मुबाइ में तो जजों को प्रभावित और परेशान करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि कई जजों के खिलाफ ही पिटीशन दायर हो जाती है। इस सम्मेलन में यह बात साफ़ झलकी कि आज न्यायाधीश समुदाय अगर किसी बात से सर्वाधिक चिंतित है तो वो है, सोशल मीडिया। ऐसा मीडिया जिसके हजारों मुंह, आंखें और कान हैं लेकिन कहीं कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। और शायद मस्तिष्क भी नहीं है। इस मीडिया ने अब मानव जीवन में इतनी भीतर तक घुसपैठ कर ली है कि किसी का इससे बचना लगभग असंभव है। यदि कोई बचा हुआ भी है तो उस पर आदिम सभ्यता का होने का टैग लग सकता है। यूं सोशल मीडिया पर जजों को लेकर अमर्यादित प्रतिक्रियाओं को लेकर पहले भी चिंता जाहिर की जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने अपना पद ग्रहण करते हुए कहा था कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया में अनियंत्रित आलोचना पर काबू करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। उह्होंने कहा, हम इस तरह की मीडिया के लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम नहीं जानते हैं लाछन लगा रहे हैं बल्कि लोगों और न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहे हैं। ऊपर से यह शिकायत भी है कि बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। उह्होंने कहा कि दरसअल फैसले की नहीं न्यायाधीश की आलोचना करना मानहानि है। पिछले साल व्हाट्सएप से जुड़े एक मामले में दलीलें मुनते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने टिप्पणी की थी कि कैसे निर्दोष लोगों को अॉनलाइन ट्रोल किया जा रहा था और कैसे गुमनाम संस्थाओं ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिष्ठा को कीचड़ में धकेलने के लिए किया था। कुछ महीने पहले, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक अलग पीठ ने बताया था कि कैसे न्यायाधीशों को भी सोशल मीडिया का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी तरह एक मामले में फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं पर एक अॉनलाइन व्याख्यान के दौरान, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया द्वारा फैलाइ जा रही असहज्यता और खासकर न्यायपालिका के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों की प्रवृत्ति के खिलाफ अपनी बात कही थी।

कि मुबई में तो जजों को प्रभावित और परेशन करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि कई जजों के खिलाफ ही पिटीशन दायर हो जाती है। इस सम्पेलन में यह बात साफ़ झलकी कि आज न्यायाधीश समुदाय अगर किसी बात से सर्वाधिक चिरंतिं है तो वो है, सोशल मीडिया। ऐसा मीडिया जिसके हजारों मुंह, आंखें और कान हैं लेकिन कहीं कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। और शायद मस्तिष्क भी नहीं है। इस मीडिया ने अब मानव जीवन में इतनी भीतर तक घुसपैठ कर ली है कि किसी का इससे बचना लगभग असंभव है। यदि कोई बचा हुआ भी है तो उस पर आदिम सभ्यता का होने का टैग लग सकता है। यूं सोशल मीडिया पर जजों को लेकर अमर्यादित प्रतिक्रियाओं को लेकर पहले भी चिंता जाहिर की जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने अपना पद ग्रहण करते हुए कहा था कि फिलाहाल सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया में अनियंत्रित आतोचना पर काबू करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, हम इस तरह की मीडिया के लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम नहीं जानते हैं लाठन लगा रहे हैं बल्कि लोगों और न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहे हैं। ऊपर से यह शिकायत भी है कि बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने कहा कि दरसअल फैसले की नहीं न्यायाधीश की आतोचना करना मानहानि है। पिछले साल व्हाट्सएप से जुड़े एक मामले में दलीलें सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक गुसा ने टिप्पणी की थी कि कैसे निर्दोष लोगों का ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा था और कैसे गुमनाम संस्थाओं ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिष्ठा को कीचड़ में धकेलने के लिए किया था। कुछ महीने पहले, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रसोगी की एक अलग पीठ ने बताया था कि कैसे न्यायाधीशों को भी सोशल मीडिया का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी तरह एक मामले में फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं पर एक ऑनलाइन व्याख्यान के दौरान, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जा रही असहिष्णुता और खासकर न्यायपालिका के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों की प्रवृत्ति के खिलाफ अपनी बात कही थी।

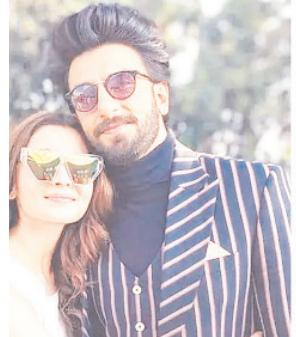


नहीं पड़ रही है। अधिव्यक्तियां संक्षिप्त होती जा रही हैं। अमेरिकी विज्ञान गत्य कथाकार इसका असिमोव की सभी भविष्यवाणियां अब मोबाइल की स्क्रीन पर साफ दिख रही हैं। हालांकि बदलाव का चक्र काफी छोटा रहा है। सबसे ज्यादा उपयोग में लाए गए एप्लीकेशन और सबसे बड़ी इंटरनेट आधारित कंपनियां हालिया इतिहास का अंग हैं। 1994 तक अमेरिजन की पहचान दक्षिण अमेरिका की केवल एक शांत नदी होने तक सीमित थी। उबर कोई सवारी नहीं, बल्कि एक विशेषण था। मेटा (पूर्व नाम फेसबुक), एक्स (पूर्व नाम टिकटर), सर्वव्यापी व्हाट्सएप, स्पॉटिफोइं, शाओफिकाई, बुकिंग डॉट कॉम, एयरबीएनबी, नेटफिल्मज इत्यादि कॉरपोरेट की दुनिया की जेनरेशन जेड में शुरा होते हैं। तकनीकी पहुंच को भारतीय परप्रेक्ष्य में देखें, तो अलग ही कहानी दिखेगी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को 1876 में टेलीफोन के लिए पेटेंट मिला। लोकिन, दो-तिवाई भारतीयों को 1990 के दशक तक फोन नहीं मिल सका था। इंटरनेट भी भारतीयों के निसीब में तब आया, जब 1995 में वीएसएनएल द्वारा मुहैया कराया गया। पर आज करीब 1.2 अरब भारतीय मोबाइल फोन और 80 करोड़ भारतीय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। 53 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप पर हैं और यू-2025 तक यह लंबे समय तक बढ़ने का उत्तम दृष्टिकोण हुए। वहाँ सर्वव्यापी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर साढ़े 11 अरब भुगतान हुए। हालांकि वैश्विक आर्थिक विकास में इंटरनेट के योगदान पर निरंतर बहस चल रही है। मैकिसे के अध्ययन के अनुसार, 2011 में इंटरनेट उपयोगकर्ता दो अरब थे, जबकि इंटरनेट आधारित इकनॉमी ने करीब 80 खरब डॉलर का योगदान दिया। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल इकनॉमी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (वैश्विक जीडीपी) में 15 फीसदी से ज्यादा योगदान देती है और यह दुनिया की वास्तविक जीडीपी से बाई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ऑनलाइन भुगतानों से ग्राहक व कंपनियां, दोनों को फायदा पहुंचा है। बैंकों को बगैर ज्यादा शाखाएं खोले, बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का मौका मिला है। म्यूचुअल फंड ने ऑनलाइन पहुंच बनाकर बचतकर्ताओं को फंड व निवेश के नए अवसर देकर अपनी पहुंच बढ़ाई है। लेकिन इसमें जोखिम भी है। जैसा अमेरिका में देखा गया, जहाँ जमाकर्ताओं ने कुछ ही धंतें में अपने खाते खाली कर दिए। हालांकि अब कंपनियां और नियामक भी इन जोखिमों से बचाकिए हैं। यूक्रेन और पश्चिम एशिया के युद्धों में इंटरनेट आधारित आक्रमक और रक्षात्मक क्षमताएं बढ़ती दिखी हैं। आज चाहे लाल सागर संघर्ष हो, इस्लाम-फलस्तीन युद्ध हो या फिर तैयार हैं, जो जेनरेटिव एआई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित हैं। एआई से पूरी दुनिया को काफी उम्मीद हैं। खासकर पहुंच, कौशल व अवसरों के क्षेत्र में विषमताओं को खत्म करने में। हालांकि यह आर्थिक, राजनीतिक और अस्तित्व संबंधी चिंताएं भी पैदा करता है। राजनीतिक स्तर पर इसकी धर्मीकरण के बढ़ने और सोशल मीडिया पर गुस्से व दुख के विस्तार की आशंका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरे महज कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक भी हैं, जो नियामकों को इस पर नियंत्रण रखने की जरूरत को इंगित भी करते हैं। यह ऑनलाइन समस्या के समाधान की कोई गारंटी तो नहीं पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा निकाय द्वारा यह परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए सुझाया गया मार्ग एवं अच्छा उपाय जरूर हो सकता है। यह टीक वैंसेंटी ही उपाय है, जैसा सुनामी आने पर प्रतिबंध और चेतावनी की व्यवस्था होती है। हालांकि जरूरत नहीं कि यह उपाय काफी साबित हो। अलबत्ता इसके लिए वैश्विक समन्वय की जरूरत होगी और, आगरा दुनिया के अग्रणी नेताओं के पास इसका कोई हल नहीं है, तो वे एआई से परामर्श कर सकते हैं।

मिटी चीक

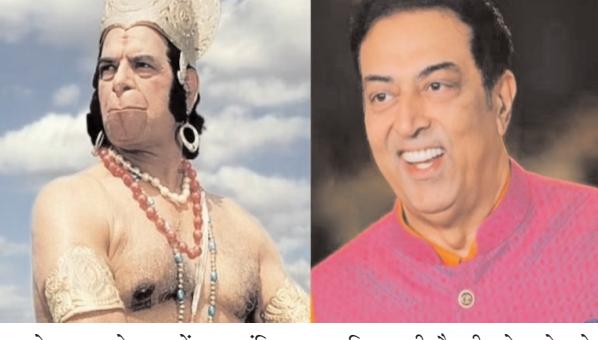
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'बैजू बावरा' पड़ी ठंडे बरसे में, बजट नहीं या कुछ और है वजह

नई दिल्ली । बीते कुछ सालों से संजय लीला भंसाली की फिल्म 'बैजू बावरा' को लेकर काफी बज बना हुआ है. ये इकलौती फिल्म है, जिसने काफी उत्तर-चदाव भी देखे हैं. संजय ने इस फिल्म की घोषणा पैंडमिक से पहले की थी. यानी की साल 2020 में. यह फिल्म एक म्यूजिकल रिवेंज ड्रामा फिल्म होने वाली है. जब फिल्म को लेकर बात होनी शुरू ही हुई थी, तभी संजय ने इसकी स्टार कास्ट को लेकर भी खुलासा कर दिया था.



डायरेक्टर का कहना था कि जालिया मृत्यु और रेजिवर सह का बोलीड रोल्स के लिए फाइनल कर चुके हैं। इसी के साथ दीपिका पादुकोण के नाम की चर्चा फिल्म में निगेटिव किरदार निभाने को लेकर हो रही थी। तीन साल बीत गए, पर फिल्म की शूटिंग का नाम-निशान नजर नहीं आ रहा है।
बंद बस्ते में गई 'बैजू बाबरा'
लॉकडाउन लगा और दुनिया रुक सी गई। जैसे ही चीजों को फिर से शुरुआत हुई, संजय ने फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर फिर से बात करनी शुरू कर दी। डायरेक्टर ने दीपिका पादुकोण

हमारे राम हैं मादी जा-यांगा
अयोध्या पहुंचकर 'टीवी
के हनुमान' के बेटे ने
कही बड़ी बात



अयोध्या अयोध्या मराम मादर प्राण प्रतिष्ठा का तयारा जार शर से चल रही हैं। एक हफ्ते तक चलने वाले इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने कई सेलेब्रिटीज पहले ही वहां पहुंचे चुके हैं। राम मंदिर उद्घाटन समारोह में रामायण पाठ और रामलीला भी की जाएगी। इसके लिए एकटर राकेश बेदी और विंदू दारा सिंह भी अयोध्या पहुंचे हैं। विंदू दिवंगत एक्टर दारा सिंह के बेटे हैं, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में हनुमान का किरदार निभाया था। उन्हें आज भी याद किया जाता है। अयोध्या नगरी पूरी तरह से सजी हुई है। शहर में दीपावली जैसा माहौल है। वहां पहुंचे राकेश बेदी और विंदू दारा सिंह ने मीडिया से बात की और अपने एक्सपरीयरिंग्स शेयर किए। एकटर्स वहां की चकाचौथी और रौनक देख बहुत खुश हुए। शहर का विकास बड़ी तेजी हुआ है, इसके बार में बात करते हुए दोनों काफी हैरान नजर आए। राकेश और विंदू ने बताया कि उन्हें रामलीला में परफर्म करने के लिए बुलाया गया है। जो कि 16 से 22 तक चलेगा। विंदू भगवान शिव का किरदार निभाते दिखेंगे। विंदू ने कहा कि, मुझे 16 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या में 'रामलीला' करने के लिए इनवाइट किया गया है। मैं भगवान शिव की भूमिका निभा रहा हूं। अयोध्या दुनिया का शीर्ष तीर्थ स्थल बन जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के भीतर भी सत्ययुग आ रहा है, ऐसा हो रहा है। ये हमारे राम जी हैं। मोदी जी और योगी जी इतना काम कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है वहां आकर, मोदी जी-योगी जी ने तो किया ही है, लेकिन बाकी भी जिन लोगों का हाथ है, उन्होंने क्या बढ़िया काम किया है। अयोध्या टॉप का धार्मिक स्थल बनने वाला है। वहीं राकेश बेदी ने कहा है। मेरे हिसाब से यहां एयरपोर्ट जो बना है, वो काबिल-ए-तारीफ है। क्योंकि जहां एयरपोर्ट होता है, विकास अपने आप बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। एयरपोर्ट बनने के बाद बहुत सारे बदलाव होंगे। नंबर बन धार्मिक स्थल बनेगा कोई डाउट नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह ग्रैंड स्केल पर होने वाला है। बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया के कई स्टार्स और सेलेब्स को इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए इनवाइट किया गया है। इनमें अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, विराट कोहली, अनुष्ठा शर्मा, कंगना रनौत, टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर समेत कई सेलेब्रिटी शामिल हैं। वहीं रामायण फेम राम-सीता-लक्ष्मण यानी अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी को भी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता भेजा गया है।

की जगह निगेटिव रोल निभाने के लिए कियारा आडवाणी और नन्यनतारा को लेकर बात की। जैसी ही बारी आई फिल्म की कास्ट को लॉक करने की संजय के सामने एक और परेशानी आ खड़ी हुई, वो ये कि संजय को इस फिल्म के लिए किसी भी स्टडियो से अप्हब्ल नहीं

स्टूडियोज से कहा कि रेणवार इस ह आर आलवा भट्ट का जा मार्केट वैल्यू है, उससे वो काफी कम फीस में इस फिल्म में काम कर रहे हैं। क्योंकि वो उनकी इज्जत करते हैं। प्यार करते हैं। पर स्टूडियोज का कहना था कि पेंडेमिक के चलते हुए 350 करोड़ रुपये एक स्पूजिकल ड्रामा फिल्म पर लगाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में संजय ने इस फिल्म को होल्ड पर डाल दिया और अभी फिल्म शायद बंद बस्ते में जाती नजर आ सकती है। हालांकि, संजय की ओर से इसपर अबतक कोई बयान जारी नहीं हुआ है।

सनी लियोनी ने किया अंकिता लोखंडे का सपोर्ट



सलिल्ब्रिटीज ने भी कहा है कि अंकिता को शो जीतना चाहिए। अब सनी लियोनी ने अंकिता का सपोर्ट किया है। उन्होंने ट्रैवीट में लिखा, अंकिता आपको बिग बॉस-17 के फिनाले के लिए शुभकामनाएं। मैं आपके साथ खड़ी हूँ। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने भी अंकिता का समर्थन किया है। श्वेता ने सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ अंकिता की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अंकिता हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम बहुत ईमानदारी से खेल रही हो और अद्भुत हो। अंकिता लोखंडे और उनके पति हैं। इन दोनों को रोज-रोज झगड़ते हैं। आए दिन उनके बीच किसी न ता था। कुछ दिन पहले अंकिता की बॉस के घर में गई थीं। इस बार दोनों मझाने की कोशिश की, लेकिन उन बाद भी अंकिता और विककी का

राम-सीता और लक्ष्मण पहुंचे अयोध्या, एल्बम ‘हमारे राम आएंगे’ की शूटिंग में हिस्सा लेंगे



आमेषक समाराह में शामिल होन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, हमारी छवि लोगों के दिलों में बनी हुई है। राम मंदिर बनने के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी ने कहा, मैं प्राण प्रतिष्ठा महोस्तव में शामिल होने के लिए सक्षम होने पर खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। देश में माहौल बेहद धार्मिक बना हुआ है। राम को नकारने वाले नहीं जानते कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और रामायण हमें मर्यादा में रहना सिखाती है। इतने सालों बाद भी रामायण सीरीज के कलाकारों का जादू आज भी बरकरार है। लोगों ने इन कलाकारों को सचमुच भगवान श्रीराम और सीता माता का स्थान दिया।

सुशात सिंह राजपूत का आखिरी फ़िल्म ‘दिल बेचाया’ का बनाने जा रहा सीध्या

जिसका नियन्ता जॉनगांगा सुशांतराज तस्वीर रख रहे थे। नेट हो जाए हमारा या ये हरा ह, लोकों पाए हैं, लोकों पाए हैं सितारे थे, जिन्होंने टेलीविजन से निकलकर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने अपने अभिन्य के दम पर बड़े-बड़े सितारों को फिल्म इंडस्ट्री में कड़ी टक्कर दी, लेकिन साल 2020 में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर ने हर किसी को हँसान कर दिया था। अभिनेता के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' रिलीज हुई थी। अब इस फिल्म को लेकर एक अपडेट सामने आया है। 'दिल बेचारा' के निर्माता मुकेश छावड़ा ने इस फिल्म का सीक्रिय बनाने का एलान किया है। निर्माता मुकेश छावड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। साथ ही वर्ष 2020 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल बेचारा' का सीक्रिय बनाने का एलान किया है। यह फिल्म दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म थी, जो उनके निधन के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से मुकेश छावड़ा ने बतार कास्टिंग निर्देशक अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। यह फिल्म जॉन ग्रीन के उपन्यास 'द



गए एक बाड़िया में, रणबीर ने आलिया के साथ अपने रिश्ते की सहयोगात्मक प्रकृति और अपने-अपने कामकाजी जीवन में एक-दूसरे को दिए जाने वाले समर्थन के बारे में बताया। कई एनिमलसीन की शूटिंग के बारे में आलिया को बताने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं उनके साथ इस पर चर्चा करता था। आप जानते हैं, उन्होंने कई सीन में मेरी मदद की है। रणबीर कपूर ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी ही थीं जिन्होंने उनके सीन को तैयार करने में उनकी मदद की थी। यह स्वीकार करते हुए कि वह किरदारों को अछाई की भावना के साथ चित्रित करते हैं, रणबीर ने बताया कि आलिया ने आत्म-सदैह के क्षणों के दौरान उन्हें आश्वस्त करने में मदद की और फिल्मांकन प्रक्रियाओं पर एक मूल्यवान परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए उन्हें ब्रेय दिया। अभिनेता ने कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने वास्तव में उस बैरोमीटर को बजाया है और कहा है कि सुनो, यह ठीक है, यह एक किरदार है, जिसका यह एक हिस्सा है। मुझे लगता है कि जहां तक इस फिल्म का सवाल है, वह बहुत

एनिमल में इंटीमेट सीन के लिए रणबीर ने आलिया से ली थी इजाजत? अभिनेता ने किया बड़ा खुलासा



नदीपार पेट्रोल पंप के सामने हुए मारपीट के मामले में सामने आया वीडियो

पुलिस अधीक्षक ने लिया संज्ञान आरोपियों की भी पहचान, जल्द होंगी गिरफतारी



कटनी, कुठला थाना अंतर्गत आने वाली बस स्टैंड चौकी के समीप नदीपार चांडक पेट्रोल पंप के सामने हुए एक प्रौढ़ के ऊपर प्राणघातक हमले को लेकर वीडियो सामने आये हैं। जिस पर पुलिस अधीक्षक अभियान कुमार रंजन ने संज्ञान में लेकर संबंधित थाने के अधिकारी को तत्काल आरोपियों की गिरफतारी के लिये आदेशित किया है। थाना कुठला द्वारा टीम का गठन कर आरोपियों की पतासाजी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जल्द ही हमला करने वाले सभी आरोपियों की गिरफतार कर लिया जाएगा। उल्लेखित है कि गत दिवस बस स्टैंड चौकी के पास चांडक पेट्रोल पंप के सामने

शंकर सिंह चौहान पिता राममिलन सिंह चौहान 55 वर्षीय पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जहाँ पर उसका उपचार जारी है। प्रौढ़ के साथ हुई घटना लूटपाट के इशारे से की गई थी। उक्त घटना को लेकर वीडियो सामने आया है जिस पर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर आरोपियों की गिरफतारी के लिए संबंधित थाना अधिकारी को आदेशित किया है। पुलिस के अनुसार जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफतारी कर ली जाएगी।

परिवहन विभाग तथा चिकित्सा विभाग द्वारा चालक, परिचालकों का नेत्र परीक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

बरवाने में चालक एवं परिचालकों का किया नैत्र परीक्षण



बड़वानी, चालक, परिचालक सामाजिक कल्याण संघ बड़वानी एवं परिवहन विभाग तथा चिकित्सा विभाग द्वारा 17 जनवरी को चालक, परिचालकों के नेत्र परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बस स्टैंड बड़वानी में उन्नत परीक्षण में 62 चालक, परिचालक संघ की ओर से श्री संजू भाई की और से श्री अशोक गोस्वामी एवं श्री प्रद्युमन तथा स्वास्थ्य विभाग से श्री अनिल राठोड़ उपरित्थि थे। उन ने परीक्षण में चश्मे की जांच हुई 23 चालक, परिचालकों को जिला चिकित्सालय बड़वानी बुलाया गया तथा एक चालक को मोतियाबिंद से ग्रासित पार जान पर उसे जिला चिकित्सालय बड़वानी में 24 जनवरी को आयोजित निःशुल्क शिविर में जांचकर मोतियाबिंद डॉपरेशन किया गया।

संचय साख संस्था में चोरी के मामले में कोर्ट ने की सुनवाई कोर्ट द्वारा दो आरोपियों को चार - चार साल का सश्रम कारावास एवं जुर्माना



नगर के जटाशांक की चौपाल पर स्थित प्रायवेट बैंक संचय साख संस्था में से साढ़े सात लाख रुपए चोरी करने के मामले में व्यापिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीरज कुमार सोनी के न्यायालय द्वारा आरोपीण भीष्म को अपाराध का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश प्रदान किया गया। अधियोजन अधिकारी अकरम मौसूमी ने बताया की संचय संस्था अर्थक्षण लेनदेन का कारोबार करती है घटना दिनांक 14 जनवरी 2019 की मध्यवाहिका को संस्था के शटर का ताला खोलकर उसके ही कर्मचारी आरोपी लक्षी ने आरोपी मध्य के साथ मिलकर संस्था में रखे हुए साढ़े सात लाख रुपयों की चोरी की थी। पुलिस द्वारा मामले की रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान किया गया था जिसमें संस्था के कर्मचारी लक्षी से पूछताछ की गई थी जिसमें उसके द्वारा घटना की रात्रि को मध्य के साथ मिलकर साढ़े सात लाख रुपए चोरी करना बताया था तथा चोरी के रूपयों में से पचास हजार रुपए आरोपी मध्य को देना बताए थे। पुलिस ने संस्था से चुराए हुए 54,685 रुपए आरोपी लक्षी के घर से बैतूल किए थे। अधियोजन के द्वारा न्यायालय के सामने संस्था के पदाधिकारियों एवं जिसी गिरफतारी साथियों सहित पुलिस/विवेचना अधिकारी अशोक अहिवरार के कथन करवाए गए जिससे संतुष्ट होकर न्यायालय द्वारा आरोपीण को कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित किया गया।

सड़क सुरक्षा समाज के तहत चलाया गया जागरूकता अभियान, कई वाहन चालकों का हुआ सम्मान। कई कों दी गई समझाईश

यातायात नियमों के बारे में सभी कों किया जाएगा जागरूक, जिसे हर किसी को जानना है जरूरी

कटनी, सड़क सुरक्षा समाज मनोने का मुख्य उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है। सड़क सुरक्षा को लेकर आमनागरिकों सहित सभी की जिम्मेदारी क्या है और हमें कैसे सड़क पर सुरक्षित रहना चाहिए। सड़क सुरक्षा समाज के दौरान यातायात नियमों की जानकारी व महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी स्कूल कालेजों और विभिन्न सार्वजनिक जगहों-जगहों पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी श्रृंखला में माध्यम नगर गेट के पास पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन, महापौर श्री मति प्रौति संजीव सूरी, यातायात सुवेदार राहुल पांडे एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में जागरूकता अभियान कार्ययोजना के तहत पुलिस द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूकता आयोजन के लिए संबंधित थाना अधिकारी ने आदेशित किया है।



कार्यक्रम चलाया गया पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन व नगर निगम महापौर श्रीमति प्रौति संजीव सूरी यातायात प्रभारी राहुल पांडेय के सानिध्य में उपनगरीय क्षेत्र माध्यवनगर चौराहा पर वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने, अधिक सवारियों नहीं फूल भेंट कर सुरक्षित वाहन सचालन के प्रति जागरूक किया। इस दौरान यातायात कर्मियों ने दो

पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने सुरक्षित रफ्तार पर वाहन चालने यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया। इसी प्रकार चौपिहया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने, अधिक सवारियों नहीं फूल भेंट के संबंध में समझाईश की गई। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन व महापौर श्रीमति

सूरी ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पूरी तरह पालन कर सुरक्षित वाहन संचालन का संदेश दिया। यातायात के नियमों का पालन सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करने के पार चलते समय यातायात के नियमों का पालन करने के लिए वाहन चालकों को यातायात करने के संबंध में वर्तमान आदेशित किया गया। इन वाहन चालकों को यातायात करने के संबंध में वर्तमान आदेशित किया गया। इन वाहन चालकों को यातायात करने के संबंध में वर्तमान आदेशित किया गया।

संकेतों में सिगनल्स, कॉसिंग, और ट्रैफिक लाइट शामिल हैं। वाहनों से उचित दूरी बनाकर रखें-सड़क पर करते समय वाहनों के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखें। यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन आपको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। दिशा का रखें ध्यान सड़क पर करते समय हमेशा सीड़ी साइड में चलें। इसके साथ ही ट्रैफिक की दिशा पर भी ध्यान रखें, ताकि हादसा ना होने पाए। वाहन चालक रखें इसका ध्यान-अगर आप बाइक सवार हैं, तो हेलमेट पहनें और गाड़ी चालकों को हमेशा सीट बेल्ट पहनकर रखनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग अगर पैदल चल रहे हैं तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ही इस्तेमाल करें। इसी की मदद से आप हादसों से दूर रहेंगे। ध्यानपूर्वक सड़क पर करते समय हमेशा ध्यानपूर्वक रहें। आसपास के वाहनों और और ट्रैफिक लाइटों का खास ध्यान रखें।

आयोजित परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र जारी करने के निर्देश - उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला

स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति प्राथमिकता से करें : उप मुख्यमंत्री

सतना रीवा, मप्र उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निर्देश दिये हैं कि स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत पदों में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की अविलंब पूर्ति करें त्वार्कृत पद जिनके लिए मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा के बाद आयोजित की जा चुकी हैं उनके अतिम परिणाम जारी करने के संबंध में विभागीय सामंजस्य के विषयों को प्राथमिकता से निराकृत करें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मन्त्रालय बलभूम में स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में बैठक में निर्देश दिये कि स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत पदों की पूर्ति कार्ययोजना को आयोजित करने के लिए अप्राप्ति का अनिवार्य बनाए रखें।



विभाग के पदों की पूर्ति सिर्फ आजीविका का माध्यम नहीं है स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक लालवानी, मध्यप्रदेश से प्राप्ति की अधिकारी एवं अधिकारी के अधिकारी की प्रतिकृति का अनावरण किया। इस अवसर पर नगरीय एवं आवास मंडल की आजीविका का माध्यम नहीं है स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक लालवानी, मध्यप्रदेश से प्राप्ति की अधिकारी के अधिकारी की प्रतिकृति का अनावरण किया। इस अवसर पर नगरीय एवं आवास मंडल की आजीविका का माध्यम नहीं है स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक लालवानी, मध्यप्रदेश से प्राप्ति की अधिकारी के अधिकारी की प्रतिकृति का अनावरण किया।

प्रदेश की पूरी आवादी से संबंधित हैं उन्होंने निर्देश दिये कि विभागीय सामंजस्य के विषयों में संबंधित अधिकारी प्राथमिकता से नियमित संपर्क

हैजा के प्रकोप से ज़द्दा रहा जाम्बिया, अक्टूबर से 400 से ज्यादा की मौत, सभी स्कूल बंद



लुसाका: दक्षिणी अफ्रीकी देश जाम्बिया हैजा के बड़े प्रकोप से ज़द्दा रहा है। पिछले साल अक्टूबर से देश में 400 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 10,000 से अधिक संक्रमित हुए हैं। हैजा के कारण देश भर के स्कूलों को बंद रखने का आदेश हैजा के कारण अधिकारियों ने देश भर के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। राजधानी लुसाका में एक बड़े

फूटबॉल स्टेडियम को उपचार केंद्र में बदल दिया गया है। जाम्बिया सरकार बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर रही है और उसका कहना है कि वह देश में प्रभावित समुदायों को प्रतिदिन 24 लाख लीटर स्वच्छ पानी उपलब्ध करा रही है। प्रतिदिन 400 से अधिक मामले किए जा रहे हैं दर्ज 'जाम्बिया परिवक्त हेल्थ इंस्टीट्यूट' के अनुसार, जाम्बिया में

ऐसा लगता है जैसे जीवन धन्य हो गया है- राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान मारे गए कारसेवकों का परिवार



कोलकाता: राम मंदिर के उद्घाटन में बमुश्किल एक सप्ताह का समय बचा है और 34 साल पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर पुलिस गोलीबारी में जन गवाने वाले कोलकाता के कारसेवकों के परिवार के सदस्यों को अब जाकर दीवाली और होली जैसे त्योहारों को खुशी का अहसास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर 1990 में कारसेवा के दौरान पुलिस गोलीबारी में राम कोठारी (22) और शरद कोठारी (20) नामक भाइयों की असामियक मृत्यु हो गई थी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर कोठारी बंधुओं की बड़ी बहन पूर्णिमा ने अपनी आह्वानों का साझा करते हुए मीडिया से कहा, "हमारा

पूरा परिवार बहुत खुश है। मेरे भाइयों के निधन के बाद से 1992 से मैंने अयोध्या की वारिक तीरथयात्रा की है और अपने दिवंगत भाइयों के करीबी मुद्दे 'राम जन्मभूमि आंदोलन%' के लिए प्रार्थना की है। मुझे विश्वास है कि मेरे भाइयों की आत्माओं को अब शांति मिलेगी। ये हम सभी के लिए दूसरी दीवाली और होली के अनुभव जैसा है।" पूर्णिमा के अनुसार उनके भाई मध्य कोलकाता के बड़ाबाजार में अपने आवास के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखा में नियमित रूप से शामिल होते थे। उन्होंने पुष्टि की, "उनके भाई कार सेवा के लिए विश्व हिंदू परिषद के अपने 43 वर्षीय पती को मारने के अलावा, बैरेट ने

आह्वान पर अयोध्या चले गए।

मोदी फिर करेंगे दक्षिणी राज्यों का दौरा करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन



नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक महीने में तीसरी बार दक्षिणी राज्यों का दौरा करेंगे और अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले महाराष्ट्र भी जाएंगे। वह यात्रा के दौरान वह हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास के साथ ही कई कार्यक्रमों की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बुधवार को बयान जारी कर यह जाकारी दी। मोदी 19 जनवरी को महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का करेंगे दौरा पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 जनवरी को महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। बयान में कहा गया है कि वह सुबह लगभग 10:45 बजे महाराष्ट्र के सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास के लिए अधिकारियों ने उद्घाटन के लिए बोर्ड के बाहर बोला लिया और इरान के बाहर बोला लिया और कार्यक्रम के प्रवक्ता माओं ने बुधवार को एक प्रेस कानूनी संस्करण का आयोगान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजिंग का

ईरान-पाकिस्तान को संयम बढ़ाने की चीज़ की नसीहत, कहा-दूसरे देशों की संप्रभुता का करें सम्मान

बीजिंग - पाकिस्तान और ईरान के बीच गतिरोध जारी है। बढ़ते तानाव के बीच चीन ने दोनों देशों से संयम बढ़ाने के लिए कहा है। चीन ने आह्वान किया कि वे तानाव को बढ़ाने वाली कार्रवाइयों पर लगाम लगाएं। दरअसल, मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद, पाकिस्तान ने ईरान में पदस्थ अपने राजदूत को वापस बुला लिया और ईरान के राजदूत को वापस बुला लिया और ईरान के राजदूत भेज दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओं ने बुधवार को एक प्रेस कानूनी संस्करण का आयोगान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजिंग का



स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योति मिश्रा द्वारा कॉम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रा. लि. प्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45 गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (मप्र.) से प्रकाशित।

प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं. : 0731-4202569 फैक्स नं. : 0731-4202569

भारतवंशी रामास्वामी को समर्थकों ने माना उपराष्ट्रपति, ट्रंप के सामने नारेबाजी

वाशिंगटन- अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए रेस शुरू हो चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भारतवंशी विवेक रामास्वामी भी ताल कॉक रहे थे। हालांकि, आयोवा कॉकस चुनाव में पिछले दो बाद उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया। खास बात ये कि ट्रंप के सामने रामास्वामी के समर्थकों ने उन्हें अमेरिका का भावी उपराष्ट्रपति कराया दिया। इस पर कद्दावर रिपब्लिकन नेता ट्रंप ने जवाब भी दिया। इससे पहले आयोवा कॉकस के परिणाम आने के बाद ट्रंप ने कहा कि वह चाहता है कि रामास्वामी ने उनके बाद उनके समर्थकों के साथ काम करेंगे। इसे भी बड़े फैसले का संकेत माना गया। ट्रंप के सामने भारतवंशी नेता कहा कि देश के लगभग आधे जिले और 10 में से नौ प्रांत हैं जो उन्होंने अपने लोगों की मौत हो रही है। करीब दो करोड़ आयोवा लोगों देश में प्रतिदिन 400 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।



देखा जा सकता है कि रामास्वामी के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रंप की मौजूदगी में हुई नारेबाजी में रामास्वामी के समर्थक वीपी-वीपी (उपराष्ट्रपति) कहते सुने जा सकते हैं। इस पर पूर्व राष्ट्रपति नेता विवेक रामास्वामी में ट्रंप की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप के समर्थन का नियन्य लिया जाता है। उन्होंने कहा, रॉन डेसेंटिस और निक्की हेली जैसे फ्लॉरिंग के गवर्नर को अपनी देशभक्त बताया और रिपब्लिकन नेताओं को भी ट्रंप का राष्ट्रपति उमीदवार बनने की रेस से बाहर होने के बाद कहा, वे अमेरिका और रिपब्लिकन पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप के समर्थन का नियन्य लिया जाता है। उन्होंने कहा, रॉन डेसेंटिस और निक्की हेली हेली जैसे फ्लॉरिंग के गवर्नर को अपनी देशभक्त बताया और रिपब्लिकन नेताओं को भी ट्रंप का राष्ट्रपति उमीदवार बनने की रेस से बाहर होने के बाद कहा, वे अमेरिका और रिपब्लिकन पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप के समर्थन का नियन्य लिया जाता है। उन्होंने कहा, रॉन डेसेंटिस और निक्की हेली हेली जैसे फ्लॉरिंग के गवर्नर को अपनी देशभक्त बताया और रिपब्लिकन नेताओं को भी ट्रंप का राष्ट्रपति उमीदवार बनने की रेस से बाहर होने के बाद कहा, वे अमेरिका और रिपब्लिकन पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप के समर्थन का नियन्य लिया जाता है। उन्होंने कहा, रॉन डेसेंटिस और निक्की हेली हेली जैसे फ्लॉरिंग के गवर्नर को अपनी देशभक्त बताया और रिपब्लिकन नेताओं को भी ट्रंप का राष्ट्रपति उमीदवार बनने की रेस से बाहर होने के बाद कहा, वे अमेरिका और रिपब्लिकन पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप के समर्थन का नियन्य लिया जाता है। उन्होंने कहा, रॉन डेसेंटिस और निक्की हेली हेली जैसे फ्लॉरिंग के गवर्नर को अपनी देशभक्त बताया और रिपब्लिकन नेताओं को भी ट्रंप का राष्ट्रपति उमीदवार बनने की रेस से बाहर होने के बाद कहा, वे अमेरिका और रिपब्लिकन पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप के समर्थन का नियन्य लिया जाता है। उन्होंने कहा, रॉन डेसेंटिस और निक्की हेली हेली जैसे फ्लॉरिंग के गवर्नर को अपनी देशभक्त बताया और रिपब्लिकन नेताओं को भी ट्रंप का राष्ट्रपति उमीदवार बनने की रेस से बाहर होने के बाद कहा, वे अमेरिका और रिपब्लिकन पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप के समर्थन का नियन्य लिया जाता है। उन्होंने कहा, रॉन डेसेंटिस और निक्की हेली हेली जैसे फ्लॉरिंग के गवर्नर को अपनी देशभक्त बताया और रिपब्लिकन नेताओं को भी ट्रंप का राष्ट्रपति उमीदवार बनने की रेस से बाहर होने के बाद कहा, वे अमेरिका और रिपब्लिकन पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप के समर्थन का नियन्य लिया जाता है। उन्होंने कहा, रॉन डेसेंटिस और निक्की हेली हेली जैसे फ्लॉरिंग के गवर्नर को अपनी देशभक्त बताया और रिपब्लिकन नेताओं को भी ट्रंप का राष्ट्रपति उमीदवार बनने की रेस से बाहर होने के बाद कहा, वे अमेरिका और रिपब्लिकन पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप के समर्थन का निय